Asha Varanasi Chapter

Asha Varanasi Chapter Address:

Village : Bhandhan Kala, Post : Kaithi

Distt. : Varanasi, U.P. – 221116

Contact Persons: Name : Vallabhacharya Pandey

E-Mail – ashakashi@gmail.com

Contact No. – 9415725428

Name : Deen Dayal Singh

E-Mail – dd.knp16@gmail.com

Contact No. – 8004804103

Facebook Page :

https://www.facebook.com/ashatrustindia/

Activities at Varanasi Chapters

- All administrative works of Asha Trust are done by Asha Varanasi Chapter.

- Scrutiny of Income Tax was cleared for the Financial year 2014-2015 and 2015-2016

- One Nation Equal Education Campaign.
- Aao Baapu Ko Jaane – Gandhi 150.

- Awareness Campaign for Right to Information, Right to Education, Right to Food, MNREGA and other Public Acts.

ONE NATION
EQUAL EDUCATION
CAMPAIGN

हमारी शिक्षा का माध्यम
हमारी मातृभाषा होनी चाहिए
एक देश समान शिक्षा
प्रणाली अभियान
हमारी शिक्षा का
पाठ्यक्रम हमारे समाज
से जुड़ा हुआ हो
ONE NATION ONE EDUCATION CAMPAIGN
एक देश समान शिक्षा प्रणाली अभियान

About Campaign

- **One Nation Equal Education Campaign is awareness campaign for better education to all children of India. This campaign aware people, children, teachers, politicians, etc. for demand better education and play a positive role in betterment of Government school.**

- **Campaign Cover 10 Districts of Uttar Pradesh. Varanasi, Chandauli, Sonbhadra, Ghazipur, Mau, Jaunpur, Azamgarh, Ballia, Lucknow and Sitapur.**

Demand of Campaign

- Compulsory follow instruction of Justish Sudhir Agarwal on 18 august 2015. “All people who take money from government treasure may enrol their children in government schools.
- Education Budget increase up to 10 percent of GDP.
- Education is not for sale, it is right of every citizen hence its is provide free to all.
- Improve all Government school’s facilities like Kendriya Vidyalaya.
- Full fill all teachers post in Government schools.

Campaign Organised

- Signature Campaign.
- Poster Display
- Awareness Campaign in Government Inter College.
- Awareness Campaign in Public Places, market and Village Chaurahas.
- Talk with Political Parties.
- Saman Shiksha Adhikar Yatra.
- Shikshak Samaan.

Signature Campaign

Poster Display

Campaign with Youths

Awareness Campaign in Public Places

Talk with Political Parties

Saman Shiksha Adhikar Yatra

सभी को मिले समान और बेहतर शिक्षा

कचहरी स्थित अम्बेडकर पार्क में शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए सभा की गई।

वाराणसी | वरिष्ठ संवाददाता

सभी को समान व बेहतर शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए रविवार को वाराणसी से मोटर साइकिल यात्रा निकाली गई। यह यात्रा पूर्वांचल के सात जिलों में तकरीबन 600 किलोमीटर का चक्रमण कर लोगों को सभी को समान शिक्षा का संदेश देगी। कचहरी स्थित अम्बेडकर प्रतिमा के पास से यात्रा को सामाजिक कार्यकर्ता डॉ.स्वाति और प्रो.महेश विक्रम सिंह ने रवाना किया।

यात्रा चंदौली, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर होते हुए छह अप्रैल को प्रधानमंत्री के आदर्श गांव नागे पहुंचेगी। यहां पर सभी को समान शि मुद्दे पर संगोष्ठी का आयोजित है। य के शुभारंभ के मौके पर हुई सभा में की गई कि सांसद और विधायक नि का 30 फीसदी सरकारी विद्यालये संसाधन बढ़ाने पर खर्च किया जाए। अवसर पर फादर आनंद, रामधीर वल्लभाचार्य, दीनदयाल सिंह, प लारी, विनय सिंह, सुरेश राठौर, सत सिंह, डॉ.नीता चौबे, जागृति रा डॉ.आनंद प्रकाश तिवारी, रंजू सिं नंदलाल मास्टर, डॉ.इंदु पांडेय अ मौजूद थे।

सभी को समान शिक्षा के लिए निकाली गयी अधिकार यात्रा

पूर्वांचल के जिलों में होगा व्यापक जन सम्पर्क

वाराणसी (काशीवार्ता न्यूज)। सभी के लिए समान एवं बेहतर शिक्षा के लिए एक देश समान शिक्षा प्रणाली अभियान के तहत सामाजिक 6 दिवसीय समान शिक्षा अधिकार यात्रा का शुभारम्भ रविवार को अम्बेडकर पार्क से किया गया। इस यात्रा के तहत पूर्वांचल के 7 जिलों में जनसंपर्क किया जाएगा। यात्रा को डा. स्वाति व प्रो. महेश विक्रम सिंह ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इस यात्रा में दो दर्जन से अधिक सामाजिक कार्यकर्त्ता शामिल रहे। यात्रा से जुड़े मंडल के सदस्यों ने कहा कि देश में सभी को एक जैसी शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए चाहे वो किसी का भी पुत्र अथवा पुत्री हो। यह तभी सम्भव होगा जब सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों व न्यायाधीशों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाएंगे तो सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में रातों-रात सुधार होगा जिसका फायदा गरीब जनता को भी मिलेगा और उसका बच्चा भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। आम जनता का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से आज समान शिक्षा अधिकार यात्रा निकाली गई है। यात्रा वाराणसी से चलकर चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर होते हुए 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री के आदर्श गाँव नागेपुर पहुचेगी जहाँ एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा जिसमे देश भर से अनेक वरिष्ठ शिक्षाविद शामिल होंगे। वक्ताओं ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18 अगस्त 2015 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय और इसे पूरे देश मे लागू किया जाय तथा निजी शिक्षण संस्थाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जाये। सभी जनप्रतिनिधि अपनी निधि से अनिवार्य रूप से कम से कम 30 प्रतिशत धनराशि अपने क्षेत्र के सरकारी/परिषदीय विद्यालयों के संसाधन को उच्च स्तरीय बनाने में व्यय करें।

समान शिक्षा अधिकार यात्रा में शामिल लोग।

विद्यालयों में शिक्षको की कमी दूर की जाय, शिक्षकों से किसी भी प्रकार का गैर शैक्षणिक कार्य न कराया जाय और प्रत्येक सरकारी विद्यालय पर अनिवार्य रूप से लिपिक, परिचारक, चौकीदार और सफाई कर्मी की नियुक्ति हो। इस दौरान फादर आनंद, डा. स्वाति, प्रो. महेश विक्रम सिंह, वल्लभाचार्य पाण्डेय, अफलातून, चिंतामणि सेठ, प्रेम कुमार, दीन दयाल सिंह, विनय सिंह, सुरेश राठौर,डा इन्दू पाण्डेय, मुकेश उपाध्याय, ए. के. लारी, राकेश, डा अनूप श्रमिक, फादर दयाकर, उर्मिला, नीति, लक्ष्मी, आफरीन, सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

Campaign in Newspapers

Quality education at govt schools will help poor students: Social activists

HT Correspondent
• htvaranasi@hindustantimes.com

VARANASI: Laying emphasis on making efforts to improve quality of government schools, many social activists demanded the UP government to ensure effective implementation of the Allahabad high court's order on sending children to government schools.

In a meeting held under 'One nation, equal education' campaign in Nadesar area, Prof Mahesh Vikram Singh, member at Akhil Bharatiya Siksha Adhikar Manch, said, "The government must ensure implementation of order by the Allahabad high court that government officers, employees, public representatives and judges should send their children to the schools run by government."

Singh said if the order given by the high court on August 18, 2015 was implemented effectively, the quality of government schools would certainly improve and help children of financially weaker sections get quality education. Non-government organisation Asha's coordinator Vallabhacharya Pandey referred to the success 'One nation, equal education' campaign had achieved so far. "Impressed by the campaign, Ajgara MLA Kailash Sonkar provided Rs 50 lakh from his MLA local area development fund for benches and tables in government primary schools last year," Pandey said.

He said Cantonment MLA Saurabh Srivastava also promised to make efforts for increasing facilities in government primary schools in his constituency. "A large section of the society is being deprived of quality education due to growing commercialisation of education. "This will be possible only when quality of education is improved at government primary schools," Singh added.

Member, District Juvenile Justice Board, Jagriti Rahi laid emphasis on improvement of government schools. "As people show interest to enrol their chil-

बेहतर शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को काशी से चलेगा अभियान

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

वाराणसी।

देश भर में समान और बेहतर शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सर्वविद्या की राजधानी से चलेगा अभियान। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाएगा और राजनीतिक दलों के एजेंडे में इसे शामिल करने के लिए दवाव वनाया जाएगा। यह फैसला रविवार को लिया गया। इस अभियान का आगाज 19 मई से होगा। पहले चरण में काशी के सभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों में जा कर ज्ञापन दिया जाएगा। यह जानकारी दी आशा ट्रस्ट के समन्वयक वल्लभाचार्य पांडेय ने दी।

उन्होंने वताया कि एक राष्ट्र समान शिक्षा प्रणाली अभियान' की प्रदेश स्तरीय वैठक रविवार को नेपाली कोठी नदेसर स्थित विश्वज्योति जनसंचार समिति सभागार में आयोजित की गई। प्रदेश के कई जिलों के प्रतिनिधियों ने इसमें शिरकत किया। विभिन्न जनपदों में समान और वेहतर शिक्षा के लिए चल रहे विभिन्न प्रयासों का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रतिनिधियों ने वताया कि विगत दिनों हस्ताक्षर अभियान, पोस्टर प्रदर्शनी, परचा वितरण, रैली, वाहन यात्रा आदि के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधियों और आम जनता को इस संवंध में जागृत करने की कोशिश की गई थी। अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच की सदस्या डा. स्वाती ने कहा कि शिक्षा के वढ़ते वाजारीकरण के कारण आज समाज का एक वड़ा हिस्सा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहा है। कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्रमशः दयनीय होती जा रही है ऐसे में हमे समाज के लोगों को सरकारी स्कूलों की वेहतरी के लिए आगे आने का आह्वान करना चाहिए।

चुनाव घोषणा-पत्र में मुद्दे को शामिल कराने पर सामाजिक संस्थाओं का जोर

किशोर न्याय वोर्ड की सदस्या जागृति राही ने कहा कि जिस प्रकार नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए अभिभावक उत्सुकता दिखाते है उसी प्रकार सरकारी प्राथमिक स्कूलों की भी गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार होने पर वच्चों के प्रवेश के लिए लोगों का झुकाव होगा। अभियान को मिल रही सफलता की चर्चा करते हुए सहयोगी संस्था आशा ट्रस्ट के समन्वयक ने कहा कि एक राष्ट्र समान शिक्षा प्रणाली अभियान के प्रयास से प्रभावित होकर अजगरा विधानसभा के विधायक ने अपनी विकास निधि से विगत वित्तीय वर्ष में 50 लाख रूपये परिषदीय स्कूलों में वेंच टेवुल लगाने के लिए प्रदान किए। इसके वाद अन्य कई जन प्रतिनिधियों ने भी अपनी निधि सरकारी स्कूलों के विकास के लिए खोल दी है। इसी क्रम में कैंट वाराणसी के विधायक ने भी कई सरकारी प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प करने का फैसला लिया है जो स्वागतयोग्य है। अन्य जन प्रतिनिधियों को ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना होगा। एक राष्ट्र समान शिक्षा प्रणाली अभियान के संयोजक दीनदयाल सिंह के कहा कि देश में सभी को एक जैसी शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए चाहे वह राष्ट्रपति की संतान हो अथवा किसान की. सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता वढ़ाने से ही यह संभव हो सकेगा. जव सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों व न्यायाधीशों के वच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाएंगे तो सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में रातों-रात सुधार होगा जिसका फायदा गरीव जनता को भी मिलेगा।

मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक महेंद्र राठौर ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में उच्च स्तर के संसाधन उपलव्ध कराए जाएं। सभी सांसद एवं विधायक अपनी निधि से अनिवार्यरूप से कम से कम 30 प्रतिशत धनराशि अपने क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों के संसाधन को उच्च स्तरीय वनाने में व्यय करें। प्रो महेश विक्रम सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय के 18 अगस्त 2015 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय और इसे देश स्तर पर लागू किया जाय। साथ ही शिक्षा का वजट वढाया जाय। उन्होंने वताया कि अगस्त 2015 के उस फैसले में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा है कि राजकीय कोष से धन प्राप्त करने वाले सभी राजकीय कर्मियों और जन प्रतिनिधियों के वच्चों को अनिवार्यरूप से सरकारी स्कूल में ही पढना चाहिए, इससे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधरेगी।

जौनपुर जिले के प्रतिनिधि शैलेन्द्र निषाद ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर की जाय, शिक्षकों से किसी भी प्रकार का गैर शैक्षणिक कार्य न कराया जाय तथा प्रत्येक सरकारी विद्यालय पर अनिवार्यरूप से लिपिक, परिचारक, चौकीदार और सफाई कर्मी की नियुक्ति हो। सभी के लिए समान शिक्षा की नीति पूरे देश में व्यवहारिक रूप से लागू की जाय। वैठक को प्रदीप सिंह, सूरज पांडेय, राजकुमार पटेल, शैलेंद्र निषाद, विनय सिंह, एके लारी, डॉ नीता चौवे, महेंद्र राठोर, गौतम सिंह, चौधरी राजेंद्र, अजीत कुमार मौर्य, जगनाथ कुशवाहा, सतीश सिंह, राम दयाल, प्रेम, मानस आदि ने भी संवोधित किया।

rights. They ... their memorandum at the Regional Office (Land ... go on token ... demonstration. The state pres- ... ed ...

Stress on need for uniform educatio

PIONEER NEWS SERVICE ■ VARANASI

After covering a distance of about 600 kilometres spanning seven districts in Purvanchal (eastern UP) and holding meetings with the people at different places, the six-day-long Saman Shiksha Adhikar Yatra on two-wheelers organised under the joint banner of Ek Desh Saman Shiksha Pranali Abhiyan and Asha Trust concluded at Nagepur, a village which was adopted by the Prime Minister under the Adarsh Sansad Gram Vikas Yojana, here on Friday.

Addressing the meeting at Asha Samajik Vidyalaya premises organised by the Lok Samiti, the speakers said that every child should be given uniform education and equal opportunity and those in the age group of six to 14 years should be given education in their mother tongue. They also said that there should be a uniform education system in the entire country and the wards of District Magistrates and peons should get an equal opportunity to explore their talents. They also said that until the senior leaders, officers and judges did not send their wards to government schools their condition would not improve. They also expressed concern over the manner in which the private English-medium schools were exploiting the guardians of the wards. They said that all the MPs and MLAs should invest 30 per cent of funds under their quota for the betterment of primary education in their respective areas.

Speaking on the occasion, Prof Mahesh Vikram Singh said that under Article 51-A every child should be provided an equal opportunit[y of] education while under A[rticle] 21-A all the children in th[e age] group of six to 14 years sh[ould] be imparted education m[anda]torily as getting it was the[ir fun]damental right. The co[nvenor] of Ek Desh Saman Sh[iksha ...] Abhiyan, Deen Dayal ... said that the purpose [of the] proposed yatra was to ... pressure on the governm[ent to] ensure uniform educat[ion ...] said that the yatra ... through Chandauli, G... Ballia, Mau, Azamga[rh ...] Jaunpur districts. It h[ad earli]er started on April ... here after garlanding ... [the stat]ue of Dr BR Ambed[kar ...] Kutchery. The pro[gramme] was inaugurated by t[he ...] representative, Dr M... Singh Patel, and presi[ded] by Surendra Singh. It [was] addressed by the coo[rdinator] Asha Trust, Vallab[h ...] Pandey, the conven[or ...] Samiti, Nandlal Mas[ter ...] Sundar Panchmukh[i ...] Desai, Chintam[ani ...] Neelam Patel, Dee[p ...] Amit, Suresh ... Mahendra, Urmila ... Vachan.

Saman Shiksha Adhikar Yatra reaching Nagepur in Varanasi on Friday. Pioneer

Poster exhibition held

PIONEER NEWS SERVICE ■ VARANASI

Under the auspices of Asha Trust, a poster exhibition was on Thursday held at Assi Ghat to ensure common education for one and all. The artists showed the need of availability of opportunity of common education to one and all through various pictures, slogans and poetries in the exhibition. The organisers Deendayal Singh, Ballabhacharya Pandey, Dr Saroj Singh, Binay Singh and Prof Mahesh Vikram said that a major part of society is deprived of qualitative education because of commercialisation of education.

The condition of government colleges is not good and thus there is need to adopt common education system and it would be possible by improving the quality of government schools, they said adding that when the children of officers, public representatives and judges would study in government schools the quality of education would improve itself benefitting the children of poor people too.

The interest of people would increase in the government schools too like they show interest in getting the admission of their wards in central or navoday schools, they said adding that there is need to bring this in practical. They demanded the restriction on private educational institutions by intermediate.

Shirish Agrawal, Suresh Kumar Rathore, Dr Indu Pandey and Suraj Pandey were mainly present on the occasion.

समान शिक्षा के लिए हस्ताक्षर अभियान

बाजारीकरण के चलते समाज का बड़ा हिस्सा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से हो रहा वंचित

अमर उजाला ब्यूरो

जौनपुर।

सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर संचालित राष्ट्र एक शिक्षा प्रणाली अभियान के तत्वावधान में मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों ने हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री को संबोधित सात सूत्री ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा।

अमीर या गरीब सभी को एक समान शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए हस्ताक्षर अभियान के आयोजकों ने कहा कि शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण के कारण आज समाज का एक बड़ा हिस्सा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहा है। कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण सरकारी विद्यालयों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के 18 अगस्त 2015 को दिए गए ऐतिहासिक फैसले का महत्व बहुत ही अधिक है। सरकारी कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों के लिए उनके बच्चों को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़वाना अनिवार्य किये जाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। संयोजक बल्लभाचार्य पाण्डेय ने कहा कि एक राष्ट्र एक शिक्षा प्रणाली अभियान का मानना है कि देश में सभी को एक जैसी शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। दीनदयाल सिंह, सूरज पाण्डेय, प्रदीप सिंह, गुरूपाल सिंह, आरती सिंह, शैलेन्द्र निषाद, बाल न्यासयालय के पूर्व न्यायाधीश संजय उपाध्याय, उदल यादव आदि लोग अभियान में शामिल रहें।

समान शिक्षा के लिए चले अभियान में हस्ताक्षर करते लोग।

हस्ताक्षर अभियान से जुटाया जन समर्थन

समान शिक्षा व्यवस्था लागू किए जाने की मांग, 200 लोगों ने हस्ताक्षर किए

अमर उजाला ब्यूरो

सैदपुर।

डायट परिसर के मुख्य द्वार पर शुक्रवार को शिक्षा का अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश, राइजिंग यूथ ट्रस्ट और आशा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। पूरे देश में सभी के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की गई।

इस अवसर पर अभियान से जुड़े वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं आशा ट्रस्ट के राष्ट्रीय समन्वयक वल्लभाचार्य पांडेय ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों मे शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 18 अगस्त 2015 को दिया गया आदेश जिसमें कोर्ट ने सभी नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके बच्चों को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़वाना अनिवार्य किए जाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया था, एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला है। इस फैसले से परिषदीय स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार की चर्चा समाज के हर स्तर पर प्रारंभ हुई थी लेकिन इसे सार्थक और व्यावहारिक स्तर तक ले जाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार की ही तरह वर्तमान सरकार भी कोई इच्छाशक्ति नहीं दिखा रही है। राइजिंग यूथ ट्रस्ट के अध्यक्ष अवनीश चौबे एडवोकेट ने कहा कि यह अभियान बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के समर्थन में है। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से सरकार से मांग की गई कि उच्च न्यायालय का 18 अगस्त 2015 के आदेश का अनुपालन प्रदेश में सुनिश्चित कराया जाय, प्रदेश में शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए, परिषदीय स्कूलों में उच्च स्तर के संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तथा सभी के लिए समान शिक्षा की नीति व्यवहारिक रूप से लागू की जाए। हस्ताक्षर अभियान में लगभग दो सौ लोगों ने हस्ताक्षर किया। अभियान में राघवेंद्र मिश्र, राकेश जायसवाल, बादल राज, सोनू यादव, आकाश बरनवाल, यशवंत सिंह, रामकिशुन कुशवाहा, इरफान अजीज खान, रामनारायन मिश्र, दीनदयाल सिंह, प्रदीप सिंह, सूरज आदि रहे।

सैदपुर डायट परिसर में शिक्षा के अधिकार के तहत हस्ताक्षर अभियान में भाग लेते लोग।

Activists moot 'one nation, one education' system

Sudhir Kumar
sudhir.kumar@hindustantimes.com

VARANASI: Call for a unified primary and upper primary education in the country gained momentum with social activists in Varanasi launching a signature campaign.

The activists also sought abolition of the private education system. They advocated for individual state boards, managed by the government, across the country under which students in the primary (1-5) and upper primary section (class five to 8) would receive common education.

This, they said, would improve education standard at government-run-primary schools besides providing a level-playing field for students from various background. There are 2.43 lakh government run schools, including primary and upper primary both in Uttar Pradesh.

However, when questioned about the future of students once they passed class 8, the activists said the matter would be looked into once the 'one India, one education system' is implemented.

Leading the campaign, social activist Dhananjay Tripathi said, "The national signature campaign commenced from Banaras Hindu University gate on July 5. It is aimed at drawing the attention of government authorities towards the need for a single education system in the country."

> At present there are two education systems: private and public. There is a sea of difference between the two as far as quality of education is concerned. y implementing 'one nation, one education' system, the differences can be reduced to a great extent
> DHANANJAY TRIPATHI, social activist

On the lines of 'one nation, one tax (GST)', there is an urgent need to implement 'one India, one education' system wherein it should be mandatory for all government authorities and public representatives to enrol their children in government primary schools, Tripathi and other activists said.

They also referred to the Allahabad high court order of August 2015 wherein it had instructed the chief secretary to ensure government employees, officials, people's representatives and those in judiciary send their children to government schools.

The activists called the decision historic and said two years had passed since the order was given and yet nothing was done. "The state government must ensure implementation of the order and come out with a plan for 'one India, one education' system," they said.

"At present there are two education systems: private and public. There is a sea of difference between the two as far as quality of education is concerned. It is an open secret that private schools are identified for imparting quality education while the quality is poor at government-run primary and upper primary schools. By implementing 'one nation, one education' system, the differences can be reduced to a great extent," Tripathi said.

CONTINUED ON P 8

Aao Baapu Ko Jaane

This year, 150 years of Gandhi ji's birth are being completed. Gandhi 150 is Celebrate in whole India as well as in other country. Asha Varanasi also do some activities.

Baapu Poster Display

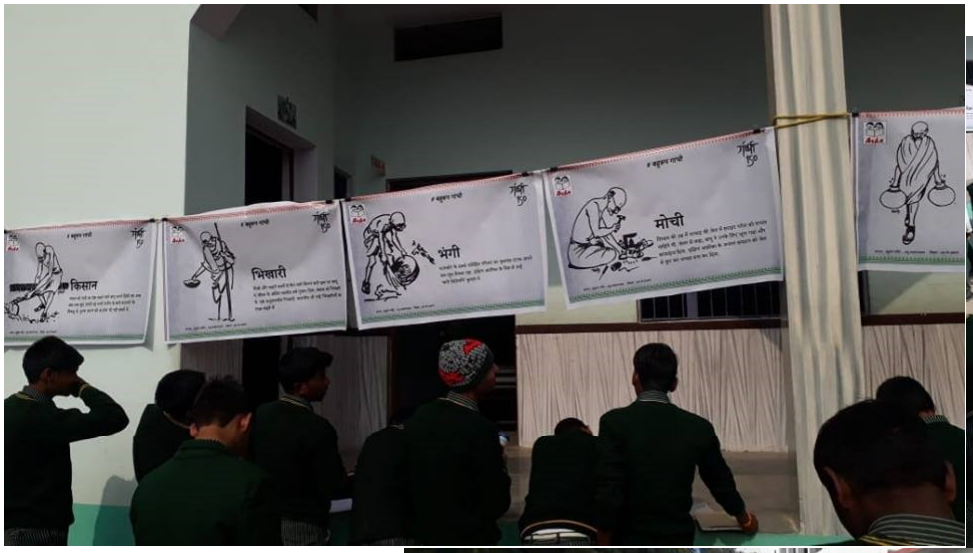

Baapu General Knowledge Competition

Prize Distribution

Thanks